

दैनिक

गाजियाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

वेल्कम इंडिया

RNI NO. UPHIN/2018/76874

नये भारत की नई सोच

वर्ष: 07 अंक: 289

शनिवार, 24 अक्टूबर-2026 (गाजियाबाद)

पेज-8

मूल्य-एक रुपया

चिन्मय मिशन केवल संस्था नहीं, एक विचारधारा है: प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी ने चिन्मय अमृत महोत्सव का किया उद्घाटन, स्वामी चिन्मयानंद के साथ मुलाकात को किया याद

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 1993 में स्वामी चिन्मयानंद के साथ हुई अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया। उन्होंने बताया कि उस बातचीत का मुख्य विषय युवाओं को सशक्त बनाना था, ताकि वे एक मजबूत और सक्षम भारत का निर्माण कर सकें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन' को संबोधित करते हुए, मोदी ने यह भी बताया कि कैसे इस आध्यात्मिक गुरु ने शिकागो में 'पालियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स' (विश्व धर्म संसद) की



शताब्दी समारोह में शामिल होने के उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को एक बेहद निजी और आध्यात्मिक अनुभव

बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक ने उन्हें स्वामी चिन्मयानंद के साथ बिताए पलों की याद दिला दी है। यह कार्यक्रम 'चिन्मय मिशन' के 75

साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, जिसकी स्थापना 1951 में इसी आध्यात्मिक गुरु ने की थी। उन्होंने आगे बताया कि स्वामी



चिन्मयानंद ने निमंत्रण स्वीकार किया और अमेरिका गए, जहाँ उन्होंने इस समारोह का प्रचार किया और लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की।

हालाँकि, 11 सितंबर को शिकागो में होने वाले इस आयोजन से कुछ हफ्ते पहले ही, 3 अगस्त को सैन डिएगो में इस आध्यात्मिक गुरु का निधन हो गया।

पीएम मोदी ने स्वामी चिन्मयानंद के अंतिम दिनों को याद किया

मोदी ने बताया कि फरवरी-मार्च 1993 के आसपास वे स्वामी चिन्मयानंद से मिले थे। उन्होंने स्वामी जी को शिकागो में होने वाले 'पालियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स' (विश्व धर्म संसद) के शताब्दी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। यह आयोजन स्वामी विवेकानंद के उस ऐतिहासिक भाषण के 100 साल पूरे होने का भी प्रतीक था, जो उन्होंने इसी मंच से दिया था। मोदी ने कहा में उन्हें अमेरिका के शिकागो में होने वाले 'पालियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स' के शताब्दी समारोह में आमंत्रित करने गया था। यह स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण के 100 साल पूरे होने का भी अवसर था।

मोदी ने कहा इस आयोजन से कुछ हफ्ते पहले, 3 अगस्त को सैन डिएगो (अमेरिका) में गुरुदेव का निधन हो गया और वे हम सबको छोड़कर चले गए। शिकागो के उस आयोजन में

अपनी मौजूदगी को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा जब 11 सितंबर को शिकागो में यह आयोजन हुआ, तो मैं सौभाग्य से वहां मौजूद था। हम सभी को वहां गुरुदेव की कमी महसूस हुई।

‘ऑफिस-ऑफिस’ सीरियल की तरह न भटके आम आदमी: मुख्यमंत्री

सही पद पर सही अधिकारी ही तैनात होगा, कार्य प्रदर्शन को जोड़ा जाएगा एसीआर व प्रमोशन से: सीएम योगी

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक आम आदमी का अपने काम के लिए कार्यालय दर कार्यालय भटकना पूरे सिस्टम पर सालिया निशान खड़ा करता है। किसी बुजुर्ग, युवा, महिला, किसान या जरूरतमंद को निराश लौटना पड़े और उसे समयबद्ध समाधान न मिले, तो लोक सेवा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। नागरिक संतुष्टि ही किसी भी लोकसेवक का रिपोर्ट कार्ड है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सक्षम, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए सही व्यक्ति को सही पद पर तैनात करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता, उपलब्धियों और सक्सेस स्टोरी को वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) तथा पदोन्नति से जोड़ने की दिशा में काम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोकभवन में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत ‘साधना श्रृंखला’ की उत्तरी क्षेत्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर तीन महत्वपूर्ण पहल की घोषणा करते हुए डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (रूपाम) को एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में



एआई, स्थानीय निकाय और सही तैनाती पर तीन प्रमुख पहल

मुख्यमंत्री ने क्षमता विकास आयोग से आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश में क्षमता विकास के लिए रूपाम को एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में सहयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा पनालिटिक्स और डिजिटल तकनीक शासन का स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं। लोक सेवकों को इन बदलावों के अनुरूप सक्षम बनाना आवश्यक है। तकनीक शासन को गति दे सकती है, प्रक्रियाएं सरल कर सकती है और निर्णयों को बेहतर बना सकती है, लेकिन प्रशासन को संवेदनशील उसका सेवा भाव ही बनाएगा।

विकसित करने, पंचायतों और नगर निकायों के कार्मिकों की क्षमता बढ़ाने तथा ‘राइट पर्सन फॉर द राइट रोल’ की अवधारणा को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र हासिल करना नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, सरल प्रक्रियाएं और बेहतर जनसेवाएं सुनिश्चित करना है। रूपाम और भारत सरकार के क्षमता

विकास आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में आठ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सीएम ने कहा कि इसके साथ ही ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर निगमों के कार्मिकों की क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। विकसित भारत और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए



केवल डिग्री और नियुक्तिपत्र से कोई दक्ष नहीं बन जाता

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में सड़क निर्माण का उद्घाटन करते हुए कहा कि उन्होंने एक सड़क को दो लेन से चार लेन बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभियंताओं ने उसे जमीन से करीब तीन मीटर ऊंचा उठा दिया। इससे आसपास की घनी आबादी के लोगों का आवागमन बाधित हो गया। शिकायत मिलने पर वह स्वयं मौके पर पहुंचे और सड़क को मूल उद्देश्य के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए। यह केवल सड़क निर्माण का मामला नहीं था, बल्कि कार्य की व्यावहारिक समझ और नागरिकों की जरूरतों को समझने की क्षमता का प्रश्न था। डिग्री और नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेना ही किसी व्यक्ति को योग्य अभियंता या सक्षम अधिकारी नहीं बना देता। नई तकनीक अपनाना, परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेना और अपने दायित्वों को समझने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है।

स्थानीय निकायों को मजबूत, जवाबदेह और नागरिक केन्द्रित बनाना होगा। पंचायतों और नगर निकाय शासन की अधिकारी एवं प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सीएम ने कहा कि इसके साथ ही ग्राम बुनियादी ढांचाया है। इनकी कार्यक्षमता मजबूत होगी, तभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘राइट पर्सन फॉर द राइट रोल’ यानी सही भूमिका के

लिए सही व्यक्ति की अवधारणा को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने क्षमता विकास आयोग से रूपाम के साथ मिलकर अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धियों, कार्य प्रदर्शन और सक्सेस स्टोरी को उनकी एसीआर तथा पदोन्नति से जोड़ने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

सेना को मिली स्वदेशी ताकत, नागपुर की कंपनी ने शुरू की 'नागास्त्र-2' एंटी-टैंक लोइटरिंग म्यूनिशन की आपूर्ति



वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। नागपुर स्थित सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड भारतीय सेना को स्वदेशी नागास्त्र-2 एंटी-टैंक लोइटरिंग म्यूनिशन प्रणाली की आपूर्ति कर रही है। यह प्रणाली बख्तरबंद लक्ष्यों पर सटीक हमला करने और आधुनिक युद्धक्षेत्र में सेना की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विकसित की गई है। कंपनी के अनुसार, नागास्त्र-2 में दिन और रात निगरानी करने वाले कैमरे तथा चार किलोग्राम का टैंडम शोट-चार्ज वारहेड लगा है। इसे 650 मिलीमीटर तक मोटे रोलड इस्तेमाल के मोड में 25 किलोमीटर तथा फायर-एंड-फाग्रेट मोड में 50

किलोमीटर तक की परिचालन क्षमता रखती है। इसकी अधिकतम उड़ान अवधि 60 मिनट है। नागास्त्र-2 की प्रमुख विशेषताओं में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेजर्स (ईसीसीएम) क्षमता शामिल है। इससे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की परिस्थितियों में, संचार बाधित होने तथा जीपीएस जैमिंग और स्मूफिंग जैसी चुनौतियों के दौरान इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। कंपनी ने बताया कि नागास्त्र-2 ने अगस्त 2026 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। परीक्षण के दौरान उपयोगकर्ताओं ने परिचालन और ईसीसीएम से संबंधित मानकों के अनुपालन का निरीक्षण किया। इससे पहले, वर्ष 2025 में भारतीय सेना ने कंपनी को लगभग 450 नागास्त्र-1आर लोइटरिंग म्यूनिशन की खरीद का आर्डर दिया था।

अरुणाचल में चीन के साथ टकराव पर सच छिपा रही है सरकार, देश को दी जाए पूरी जानकारी: खरगे

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के साथ भारतीय सैनिकों के टकराव की जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें देश को गुमराह करने की बजाय संसद तथा जनता को पूरा सच बताना चाहिए। श्री खरगे ने शुक्रवार को यहां एक बयान में कहा कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ लगातार हो रहे टकराव की पुष्टि की है। उन्होंने पूछा कि डोकलाम और गलवान के बाद क्या यह एक और गंभीर टकराव हो रहा है। उनका यह भी कहना था कि अगस्त में तक्सिंग के पास चीनी घुसपैठ की खबरें आई थीं और वाचा-दमाई में कोर कमांडर स्तर की बातों के 47 दिन बाद भी टकराव जारी रहने की खबरें हैं।

उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इस मामले में देश को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि क्या भारत की गश्त करने के पहुंचे इस क्षेत्र में प्रभावित हुई है। श्री खरगे ने प्रधानमंत्री से चीन को बार-बार क्लीन चिट देना बंद करने और देश



के सामने स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जवाबदेही जरूरी है, न कि कूटनीतिक मुलाकातों और गले मिलना। चीन पर आर्थिक निर्भरता को लेकर उन्होंने कहा कि गलवान में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद वित्त वर्ष 2020-21 से चीन से आयात में 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 112.16 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वीकार कर चुकी हैं कि चीन भारतीय निर्यात में बाधा डालता है। उन्होंने चीन से जुड़े निवेश पर प्रतिबंधों में ढील देने और पात्र चीनी कंपनियों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) और ब्रिक्स के शिक्षक सम्मेलनों में भी दोनों पक्षों के बीच संपर्क हुआ है। बैठकों के क्या ठोस परिणाम निकले और क्या मई 2020 से पहले की गश्त संबंधी पहुंच पूरी तरह बहाल हुई है। हमको सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जवाबदेही भी जरूरी है। प्रधानमंत्री को विपक्ष पर हमला करने की बजाय संसद और देश की जनता को पूरी स्थिति से अवगत कराना

चाहिए। इस बीच, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार जून-जुलाई से अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों से जुड़ी खबरों को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कर्पू ने अब पुष्टि की है कि भारतीय सैनिकों और चीनी सेना के बीच टकराव जारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आईटीबीपी सहित सभी बहादुर सैनिकों को सलाम करती है और जो विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में ऐसी सरकार है जो न सैनिकों की शहादत को सलामी देती है और न उनकी बहादुरी को शाबाशी। उनका कहना था कि कि वर्ष 2020 में गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद श्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट दी जिसके कारण लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन तुम्साहस दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के महानिदेशक के बयान के तुरंत बाद सूत्रों के हवाले से खबरें चलने लगी कि बल इस मुद्दे पर जल्द आधिकारिक बयान जारी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो सवाल है कि क्या सरकार की ओर से सच्चाई को सामने आने से रोकने की कोशिश तो नहीं है।

'उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहे सेना', सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय सेना को दीर्घकालिक रणनीति के लिहाज से काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही वर्तमान व उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में सफलता के लिए एकीकृत दृष्टिकोण बेहद जरूरी है।

राजनाथ सिंह ने सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए शीर्ष सैन्य नेतृत्व से वर्तमान भू-राजनीतिक एवं क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखने और हर संभावित चुनौती के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। उन्होंने अगले 20-30 वर्षों को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत पर जोर दिया, साथ ही तात्कालिक एवं उभरती हुई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भी समान रूप से तैयार रहने को कहा।

नई दिल्ली में हुए इस सम्मेलन में शीर्ष सैन्य कमांडरों ने चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर सेना की युद्धक तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने सेना की भविष्य की तैयारियों को मजबूत करने के लिए जमीनी युद्ध के सिद्धांत



(लैंड वारफेयर डाक्टरीन) भी जारी किए। उन्होंने कहा कि रणनीतियों को गतिशील एवं लचीला होना चाहिए, ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार समय रहते उनमें बदलाव किया जा सके। बदलती परिचालन परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए सशस्त्र बलों की सलाहना करते हुए उन्होंने कहा कि नवोन्मेषी सोच, बेहतर तालमेल और उत्कृष्ट समन्वय के साथ आधुनिक हथियारों ने आपरेशन सिंदूर की सफलता में योगदान दिया। इस अभियान ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। रक्षा मंत्री ने सेना के पुनर्गठन प्रयासों की सराहना की और झेन व आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया।

संपादक की कलम



करंट कर्मचारियों को, झटका जनता को!

लो कर्तव्य में सरकार का सबसे बड़ा दायित्व जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार जैसी सेवाएं किसी भी सम्यक् समाज की आधारशिला होती हैं। इन सेवाओं की गुणवत्ता ही प्रशासन की कार्यक्षमता और जनबादेंदी का पैमाना चलता है। लेकिन जब सरकारी व्यवस्था जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, तो लोग बेहतर विकल्प तलाशने लगते



ललित शर्मा
संपादक

बढ़ी। सरकारी अस्पतालों में लंबी कतारों और संसाधनों की कमी से परेशान अनेक लोग नौ नौ निजी अस्पतालों का रुख किए। इन उद्धारणों का अर्थ यह नहीं है कि सरकारी संस्थान आधुनिक हो गए हैं या निजी क्षेत्र हमेशा बेहतर सेवाएँ देता है। सरकारी संस्थानों ने दूर-दराज के क्षेत्रों तक सुविधाएँ पहुँचाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्तरा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र में महँगी सेवाओं, मुनाफे की प्राथमिकता और उपभोक्ताओं की आर्थिक क्षमता के आधार पर सुविधाओं में अंतर जैसी चुनौतियाँ भी हैं। इसलिए असली ख्याल सरकारी बनाम निजी का नहीं, बल्कि बेहतर, सुलभ, किफायती और जवाबदेह सेवाओं का है। यही दूसरी बिजली व्यवस्था पर भी लागू होती है। और नागरिक के लिए बिजली को कई वित्तासिद्ध नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। बच्चों की पढ़ाई, किसानों की सिंचाई, छोटे दुकानदारों का कारोबार, उद्योगों का उत्पादन और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल—सब कुछ किसी न किसी रूप में बिजली पर निर्भर है। बिजली की आपूर्ति बाधित होने का अर्थ केवल घर में अंधेरा होना नहीं है। इससे कामकाज रुकता है, आर्थिक नुकसान होता है और सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है। देशभक्त हार महंजी बिजली का बिल भरते हैं। बदले में उसकी अपेक्षा होती है कि उसे निर्धारित दरों पर बेहतरसेमद आपूर्ति मिले। उसे इस बात से कम मतलब है कि बिजली की व्यवस्था सरकारी हाथों में है, यानी निजी क्षेत्र के पास। उच्च निर मूल्यपूर्ण यह है कि घर में पंखा चलते, घनी कठोर काम करके, बच्चे पढ़ सकें और कारोबार बिना आवश्यकता रुकबंद के चलते रहें। जब बिल न भरने पर उपभोक्ता को कारवाई का सामना करना पड़ सकता है, तो सेवा बाधित होने पर संबंधित व्यवस्था की जवाबदेही भी तय होने पर सही रहता। हरियाणा में हीट के कई हिस्सों में बिजली क्षेत्र के निजीकरण और कर्मचारी संगठनों की माँगों को लेकर बहस होती रही है। निजीकरण के समर्थक बेहतर प्रबंधन, निवेश, तकनीकी सुधार और कार्यकुशलता की उम्मीद करते हैं। वहीं कर्मचारी संगठनों का आशंका रहती है कि निजीकरण से रोजगार की सुरक्षा, सेवा शर्तों, कर्मचारियों के अधिकारों और उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन आशंकाओं को अन्वेषण नहीं किया जा सकता। बिजली जैसी आवश्यक सेवा में किसी भी बड़े बदलाव से पहले उसके आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव का आकलन जरूरी है।

रास पूर्णिमा (गोपी छंद)

मोनिका डाग

कविता



शरद पूर्णिमा की रश्मियाँ, अमृत र आनंद र बहाती है,
शुभागमन में शरद ऋतु के, प्रकृति गीत गुनगुनाती है ।

देख आज कण-कण धरा का, पूर्ण रसामृत से है भरा,
सुधाकर सोलह कला लिए, व्योम में झूमता मुस्कुरा,
श्वेत शांति का ये तोहफा, धरा को निशाकर से मिला,
दिव्य अमिय माधुर्यता से, रोम-रोम पुलकित हो खिला,
चौदनी शरद पूर्णिमा की, प्राण शुद्धि को बढ़ाती है,
शुभागमन में शरद ऋतु के, प्रकृति गीत गुनगुनाती है

धवल आभ ने ब्रह्माण्ड में, तिलिस्म प्रेम का बिखेरा,
स्पर्श ने चॉदनी के नया, खुशी का भाव है उकेरा,
भूलकर दुःख चकोर यहीं, किसी प्रेम राग में खोया,
पारिजात ने कपोलों में, नेह र आनंदर को पिरोया,
रास पूर्णिमा की रात ये, प्रसन्नता को जगाती है,
शुभागमन में शरद ऋतु के, प्रकृति गीत गुनगुनाती है

हुई भक्ति में श्री कृष्ण की, भाव विभोर सभी गोपियों,
अनूठी कृपा सांवर की, नवान्न पूनम करें खुशियाँ,
भक्त खीर का प्रसाद बना, प्रेम से भोग है लगाते,
भजन रातिजोगा कर सभी, हरिप्रिया को है मनाते,
कौमुदी पूर्णमा सभी को, शक्ति सम्पन्न बनाती है,
शुभागमन में शरद ऋतु के, प्रकृति गीत गुन्गुनाती है

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक ललित कुमार द्वारा वेलकम इंडिया प्रेन्टर्स, 1/26, साउथ साइड, जी टी रोड, गाजियाबाद-201001 से मुद्रित कराकर ग्राउन्ड फ्लोर, दुर्गा टॉवर, आर.डी.सी. राजनगर, गाजियाबाद 201002 से प्रकाशित किया। संपादक : ललित शर्मा

सम्पर्क सूत्र: 9891116568

किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा गाजियाबाद न्यायालय में ही होगा।

संपादकीय

व्हाट्सऐप चैट से हत्या साबित नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला



शव एक खुले मैदान में मिला। शव के पास उसकी मोटरसाइकिल और रस्सी भी थी। उसकी मोटरसाइकिल के बाइरामला हल्ला का मानकर अज्ञात व्यक्तियों ने खिलफा प्रार्थमिकी दर्ज की गई। पुलिस जांच के दौरान अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कुसुमपाल साहू को इस आरोप से जोड़ने का प्रयास किया। जांच में अभियोजन पक्ष के दो गवाहों, जिन्हें न्यायालयीन प्रकांड में पीडब्ल्यू-5 और पीडब्ल्यू-6 कहा गया, के मोडबल में जबरन किए गए। फॉरेंसिक जांच में उनके फोन के बीच 7 और 8 फरवरी 2019 की दरमियांन रात एक व्हाट्सएप संदेश मिलने की बात सामने आई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उस संदेश में मृतक और आरोपी के बीच कथित विवाद तथा भारपीट का उल्लेख था। अभियोजन ने इस संदेश को आरोपी की कथित सलिलता से जोड़ने के लिए

महत्वपूर्ण आधार बनाया इसके अतिरिक्त, आरोपी के घर से लोहे की रॉड, पेचकस, खुन के निशान वाली शर्ट और खुन लाले मिश्री मिलने का दावा किया गया। निचली अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (साक्ष्य मिटाने से संबंधित अपराध) के तहत दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि बरकरार रखी फिर इसके बाद आरोपी ने विश्वस्तार से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साथियों बात आरोप सम अदालत ने व्हाट्सएप चैट को पर्याप्त सबूत क्यों नहीं माना? इसकी समझने के करें तो इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि दोनों गवाहों ने कथित घटना के बारे में अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आरोपी और मृतक के बीच उग्र रात का कथित झगड़ा को अपनी आंखों से देखने की की पुष्टि नहीं की। संदिग्ध भेजने के आरोप

संयुक्त राष्ट्र की साथ पर सवाल, सुधार से ही बचेगी प्रतिष्ठा



ललित गर्ग
लेखक

संयुक्त राष्ट्र दिवस केवल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना का उत्सव नहीं, बल्कि विश्व शांति, मानवाधिकारों, न्याय, समानता और राष्ट्रों के बीच सहयोग के उन संकल्पों को याद करने का अवसर है, जिनके आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद इस संगठन की स्थापना हुई थी। 24 नवंबर, 1945

को संयुक्त राष्ट्र चारों तरफ लगे होने के साथ दुनिया ने एक ऐसी व्यवस्था की उम्मीद की थी, जिसमें युद्ध की जगह संवाद, टकराव की जगह सहयोग और शक्ति के स्थान पर आज्ञा को प्राथमिकता मिलेगी। किंतु उन, जब दुनिया अनेक युद्धों, आतंकवाद, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और मानवीय संकटों से जूझ रही है, तब संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, निष्पक्षता और प्रभावीता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। जिस संगठन से विश्व समुदाय को कार्य की अपेक्षा थी, उसकी काय्यप्रणाली ही संदेह के घेरे में आने लगे तो आत्मसंभन अनिवार्य हो जाता

है। संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों को नकारना उचित नहीं होगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सन्धियों के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराया, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के माध्यम से मानवीय गरिमा के वैश्विक मानक स्थापित किए और अनेक देशों में शांतिस्था अभियानों के जरिए स्थिरता बहाल करने का प्रयास किया। विश्व स्वास्थ्य, बाल कल्याण, शिक्षा कार्याधिन्यों की सहायता तथा सतत विकास के क्षेत्रों में उसकी विभिन्न संस्थाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके बावजूद मूल प्रश्न यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र अपने सबसे महत्वपूर्ण दायित्व-युद्ध रोकने, आतंकवाद पर प्रभावी अंकुश लगाने और सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार करने में अपेक्षित सफलता प्राप्त कर पाया है? आज का अनुभव इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता।

संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी संसजोरी उसकी सुरक्षा परिषद की संरचना में दिखाई देती है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को प्रायः वीटो अधिकार के बार वैश्विक शांति में अधिक उनके राष्ट्रीय हितों की रक्षा का माध्यम बन जाती है। जब कि सयुद्ध या मानवीय त्रासदी पर प्रभावी निर्णय भू-राजनीतिक तर्कोंद्वारा के लिए रुक जाता है, तब संयुक्त राष्ट्र की घोषणाएं और अपीलें अपनी निष्पक्ष शक्ति खोने लगती हैं। गाजा, यूक्रेन और सीरिया जैसे विषयों ने यह प्रसंग तोखा कि क्या विश्व शांति का दायित्व निभाने वाला संगठन वास्तव



में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम है? विवर्धना यह है कि दुनिया बदल गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की निर्णय व्यवस्था काफी हद तक उसी पुराने शक्ति-संतुलन में बंधी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर उठते प्रश्नों का ताजा उदाहरण दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह डी-कंपनी से जुड़ा विवाद है। आतंकवाद और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक बेन साला की रिपोर्ट में डी-कंपनी की हथभारत आधारित तहकूद अपराधिक गिरोह बताया गया। भारत ने 21 अक्टूबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में इस विवरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे तथाकथित रूप से गलत और संगठन की साख को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। भारतीय प्रतिनिधि रघु पुरी ने दाऊद के आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े इतिहास और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में दर्ज तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि दाऊद भारत में वांछित

अपराधी है और भारत के अनुसार पाकिस्तान में रह रहा है।

यह प्रकरण इसलिए गंभीर है कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील विषय पर तथ्यात्मक शुद्धता और निष्पक्षता सर्वोपरि होनी चाहिए। किसी आतंकवादी गिराह की भौगोलिक पहचान को लेकर गलत या अधूरी जानकारी सामने आना केवल एरिपोर्ट की त्रुटि नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी प्रयासों की विश्वसनीयता का प्रश्न है। हालांकि किसी एक रिपोर्ट की गलती से पूरे संगठन के प्रत्येक कार्य को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी त्रुटियाँ जो जांच, सुधार और जावबादेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। विशेष प्रतिवेदन की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, किंतु स्वतंत्रता का अर्थ तथ्यों और उद्देश्यात्मक से मुक्त होना नहीं है। इस प्रकार मानवाधिकारों के मामलों में भी संयुक्त राष्ट्र को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। मानवाधिकार

लोकतंत्र की व्यथा और दुर्दशा : जितने राजनीतिक दल उतनी समीक्षा



संजीव ठाकुर
लेखक

राजनीतिक दल अब देश और जनहित को पीछे छोड़कर केवल अपनी सत्ता और राजनीतिक लाभ को सर्वोपरि रखने लगे हैं। वैचारिक बहस और विकास के मुद्दों पर बात करने के बजाय, चुनाव अब भावनाएँ भड़काने, धुविकरण और मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटने तक सीमित हो गए हैं।

लोकतंत्र किसी देश की शासन व्यवस्था मात्र नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय का जीवंत प्रतिबिम्ब होता है। इसकी वास्तविक शक्ति राजनीतिक दलों की संख्या में नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा, जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन में निहित होती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में अनेक राजनीतिक दलों का होना स्वाभाविक है। यहाँ

माषा, संस्कृति, क्षेत्र, सामाजिक संरचना और आर्थिक परिस्थितियों की विविधता है। इसलिए विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को स्वर देने के लिए अनेक दलों की आवश्यकता से इनकारा नहीं किया जा सकता। किंतु जब राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ने के साथ जनहित के प्रश्न पीछे छूटने लगें, विचारधारा की जगह अवसरवाद ले ले और राजनीति का मूल उद्देश्य जनसेवा के बजाय सत्ता प्राप्त करना बन जाए, तब लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। आज प्रश्न यह नहीं है कि देश में कितने राजनीतिक दल हैं, बल्कि यह है कि वे लोकतंत्र को कितना मजबूत बना रहे हैं और आम नागरिक के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। संविधान के प्रथक वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देकर उसे शासन व्यवस्था में भागीदारी का अवसर दिया। यह अधिकार केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी आकांक्षाओं और असहमति को व्यक्त करने की शक्ति भी है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को हूजना का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया था। इस विचार में लोकतंत्र की संपूर्ण आत्मा समाहित



है। यदि शासन जनता के नाम पर चले, लोकतन्त्र उसकी प्राथमिकताओं में जनता की समस्याएँ ही शामिल न हों, तो लोकतन्त्र को आबरी स्वरूप देने से सुरक्षित रहने, उसकी आत्मा कमजोर होने में लगती है। जनता को केवल चुनाव के समय याद करना और उसके बाद उसकी कठिनाइयों से विमुख हो जाना, कर्तव्यपूर्ण भावना के विपरीत है।

भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में स्पष्ट चेतावनी दी थी कि हमें केवल राजनीतिक लोकतन्त्र को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि राजनीतिक लोकतन्त्र को सामाजिक लोकतन्त्र भी बनाना होगा। उन्होंने स्पष्ट स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सामाजिक लोकतन्त्र के आधारभूत सिद्धांतों के रूप में स्थापित किया।

सिद्धांत बताया था। उनका यह कथन अत्यंत आज़ भी राजनीतिक दलों के लिए अत्यंतमध्यम का अवसर है। आंबेडकर ने यह भी कहा था कि संविधान किताब ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ है कि लोकतंत्र की सफलता केवल संविधान और संस्थाओं पर निर्भर नहीं करती; यह उन लोगों के चरित्र, आचरण और उत्तरदायित्व पर भी निर्भर करती है। जिन्हें जनता शासन की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अनेक बार यह दिखाई देता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जगह कटुता बढ़ती है। यह है लोकतंत्र में विपक्ष का काम।

से जुड़े गवाह ने यह भी कहा कि उसने ऐसा संदेश भेजा ही नहीं था। खुशियम कोर्ट के सामने इसलिफ केवल यह साबित नहीं था कि मोडाल्फ फोन में संदेश मौजूद था या नहीं, बल्कि यह भी था कि संदेश किसने लिखा, वह किस जानकारी पर आधारित था और वह उसने वीजॉ घटना वास्तव में हुआ थी न्यायालय ने माना कि पीडब्ल्यू-5 और पीडब्ल्यू-6 के बीच संदेशों का आदान-प्रदान यह साबित नहीं करता कि मृतक उस रात आरोपी के घर मौजूद था अथवा आरोपी ने उस पर हमला किया था। संदेश अधिकतम संदेह पैदा कर सकते थे, लेकिन संदेह और दोष सिद्ध करने के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। अपराधिक न्याय व्यवस्था में दोष सिद्ध के लिए अभियोजन को अपराध संदेह से परे साबित करना होता है। साथियों बात अगर हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 6: एक ही घटनाक्रम का हिस्सा होना क्यों जरूरी? इसकी समझने की करें तो, इस नियमों का कानूनी महत्व भारतीय 34थी अधिनियम, 1872 की धारा 6 की व्याख्या में भी है। यह प्रावधान सामान्यतः उन तथ्यों को प्रासंगिक बनाने से संबंधित है जो किसी निवृत्त तथ्य या घटना से इतने निजता से जुड़े हों कि एक ही लेन-देन या घटनाक्रम का हिस्सा माने जा सकें। ऐसे असपर रेसर गेस्टपा के सिद्धांत के रूप में समझाया जाता है। अदालत ने पाया कि इस मामले में मौत का सही समय ठोस साक्ष्य से

निर्धारित नहीं हो पाया था। इसलिए यह स्थापित करना कठिन था कि विवादित संदेश अपराध के समय या उसके अपरासापेक्ष भेजे गए थे और उसी घटनाक्रम का हिस्सा थे। धारा 7 के संदर्भ में भी अदालत ने स्पष्ट किया कि संदेशों के तकनीकी रूप से एक फोन से दूसरे फोन तक पहुंचने की बात, उसमें वर्णित घटना की सत्यता को अपने आप साबित नहीं करती। संदेश भेजने वाले की जानकारी का स्रोत और उसके कथन का आधार जानना जरूरी था। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए: किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अस्तित्व साबित करना और उस रिकॉर्ड में लिखी बात को सच साबित करना दो अलग-अलग प्रश्न हैं। साथियों बात अगर हम खून के निशान, बरामदगी और डीएनए जांच पर भी उठे साल्ट इसको समझने की करें तो, सुप्रीम कोर्ट ने केवल केबलस्ट्रॉप संदेशों का परीक्षण ही नहीं किया, बल्कि अन्य परिस्थितिनयन साधनों की विश्वसतिजय भी जांची। आरोपी के घर से खून लगी मिट्टी और अन्य वस्तुओं की बरामदगी के संबंध में गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे। एक जल्दी गवाह के बयान से इस बात पर संदेह पैदा हुआ कि मिट्टी वास्तव में आरोपी के घर से मिली थी या उस खुले मैदान से, जहां शव बरामद हुआ था। इसके अलावा, बरामदखून की मृतक से जोड़ा गया निर्णायक डीएनए मिलान उपलब्ध नहीं था।

किसी राष्ट्र की सीमाओं में कैद विषय नहीं हैं, लेकिन उसकी रक्षा के नाम पर किसी देश के विरुद्ध निष्कर्ष निकालने से पहले प्रमाणों, परिस्थितियों और आतंकवाद से प्रभावित नागरिकों के अधिकारों को समान गंभीरता से देखना चाहिए। आतंकवाद के पीड़ितों को मानवाधिकार की उन्ने ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, जितने आतंकवाद के निपटने के दौरान किसी निर्दोष व्यक्ति के अधिकार। यदि आतंकवाद के प्रायोजकों, हिंसा के जिम्मेदार लोगों और पीड़ितों के प्रति दृष्टिकोण में असमानता दिखाई देती है, तो निष्पक्षता पर संदेह स्वाभाविक है। संयुक्त राष्ट्र के सामने एक दूसरी बड़ी चुनौती प्रतिनिधित्व की समस्या है। भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों की बढ़ती वैश्विक भूमिका के बावजूद सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं हो पाया है। दुनिया की वर्तमान राजनितिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली व्यवस्था के बिना संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिक बनाना कठिन है। आतंकवाद के विरुद्ध साझा रणनीति, युद्धविराम की प्रभावी व्यवस्था, मानवीय सहायता की निर्बाध उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय कानून के समान अनुपालन को भी प्राथमिकता देनी होगी। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर आत्ममंथन का वास्तविक अर्थ केवल उसकी उपलब्धियों का गुणगान करना नहीं, बल्कि उसकी कमियों को

स्वीकार कर सुधार का संकल्प लेना है। संघटन को अपने निर्णयों में तत्कालिक सुधार, अधिकारियों की जवाबदेही और सभी देशों के प्रति निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी। वोटों अधिकार के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने, सुरक्षा विरुद्ध के विस्तार और आतंकवाद के बिकरुद दोहरे मानदंड समाप्त करने की दिशा में ठोस पहल करनी होगी। आज जब दुनिया युद्ध, आतंकवाद, हिंसा, मानवीय संकट और राष्ट्रों के बीच बढ़ते विषयों के दौर से गुजर रही है, तब संयुक्त राष्ट्र दिवस की प्रासंगिकता और जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यह दिवस केवल एक अंतरराष्ट्रीय संघटन की स्थापना का स्मरण नहीं, बल्कि विश्व शांति, सह-अस्तित्व, मानवीय गरिमा और वैश्विक सहयोग के संकल्प को दोहराने का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र को अपनी निष्पक्षता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के माध्यम से यह सिद्ध करना होगा कि वह शक्तिशाली राष्ट्रों के हितों का नहीं, बल्कि समूची मानवता के व्यक्त और सुरक्षा का प्रहरी है। उसका न्यायवर्तिक दायित्व यहूदी रोकना, आतंकवाद पर अंकुश लगाना और शांति का मार्ग प्रशस्त करना है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया पर शासन करना नहीं, बल्कि दुनिया को युद्ध, अन्याय और विनाश से बचाने में सहयोग देना है। उसकी प्रतिष्ठा केवल उसके घोषणापत्रों से नहीं, बल्कि संसदीय की घड़ी में तिक गैर निष्पक्ष और प्रभावी कार्यों से तिक होगी।

सरकार को नीतियों की समीक्षा करना, गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित करना और जनता के समक्ष वैकल्पिक नीतियों प्रस्तुत करना है। वहाँ सत्तापक्ष का दायित्व है कि वह जनजादेश को अहंकार का आधार न बनाए और अलोचन को लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा समझे। लेकिन जब विरोध केवल विरोध के लिए होने लगे, प्रत्येक सरकारों निर्णय को बिना तथ्यपरक विश्लेषण के नकार दिया जाए अथवा सत्ता पक्ष हर अहंकारी को अपनी प्रतिष्ठा पर आक्रमण समझने लगे, तब लोकतांत्रिक संवाद प्रभावित होता है। संसद और विधानसभाओं जसमर्यादों पर गंभीर बहस के मंच हैं, न कि केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के अवसर। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे वहाँ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्यांवर्ण और आर्थिक असमानता जैसे प्रश्नों पर सार्थक चर्चा करें। राजनीतिक दलों की समीक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार उनकी आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या दलों में योग्य और ईमानदार कार्यकर्ताओं को योग्य बढ्ने का अवसर मिलता है ? क्या संगठनात्मक निर्णयों पर परदर्शी ढंग से लिए जाते हैं ? क्या नेतृत्व का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है ? अथवा कुछ प्रविराओं, व्यक्तियों और भावशास्त्री समूहों के

हाथों में निर्णय लेने की शक्ति केन्द्रित रहती है? लोकतंत्र का दवाक लेने वाले दलों को अपने भीतर भी लोकतंत्र को पालन करना चाहिए। यदि किसी दल में विचारों की स्वतंत्रता और आंतरिक असम्मति के लिए स्थान नहीं है, तो उससे व्यापक लोकतंत्रिक संस्कृति को मजबूत करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव, चुनावी खर्च की अपारदर्शिता तथा उम्मीदवारों के चयन में अनुचित प्रभाव की आशंकाएँ भी लोकतंत्र के सामने गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। जब चुनाव में धन और प्रचारों की क्षमता को योग्यता, समानता तथा जनसेवा से अधिक महत्व मिलने लगे, तब सामान्य नागरिक की राजनीतिक भागीदारी प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक चर्चे की पारदर्शिता, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की सार्वजनिक जाँचकारी और चुनावी नियमों का प्रभावी पालन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। इसी प्रकार जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर समाज को बाँटने वाली राजनीति से भी सावधान रहना ही आवश्यकता है। विविधता भारत की शक्ति है, लेकिन जब इसी विविधता को सामाजिक तनाव और चुनावी लाभ का साधन बनाया जाता है, तब राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक-सद्भाव प्रभावित होते हैं।

उठाएगी। फिलहाल वायरल वीडियो के बाद क्षेत्र में बाघ को लेकर चर्चा और दशरथ का माहौल बना हुआ है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अकेले खेतों की ओर जाने से बचें, समूह में आवाजाही करें और वन्यजीव दिखाई देने पर उसके करीब जाने या उसका पीछा करने के बजाय वन विभाग को सूचना दें।

ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव और आसपास के खेतों में निगरानी बढ़ाएंगे तथा बाघ की तलाश के लिए टीम भेजने की मांग की है। किसानों का कहना है कि धान की फसल तैयार होने के कारण खेतों में जाना उनका मजबूरी है, लेकिन बाघ की मौजूदगी की आशंका से वे डरे हुए हैं। ऐसे में वन विभाग की ओर से समर्थन रहते आवश्यक कदम उठाना जरूरी है, ताकि किसी भी अग्रिय घटना को रोका जा सके। ग्रामीणों की उम्मीद है कि विभाग मामले को गंभीरता से लेते हुए बाघ की लोकेशन का पता लगाएगा और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित इंतजाम करेंगी।

केएनएमआईटी के विद्यार्थी को केपीएमजी कनाडा में एक करोड़ वार्षिक पैकेज

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। डॉ. के. एन. मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केएनएमआईटी) को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ईसीई) विभाग के विद्यार्थी वैभव यादव की असाधारण प्लेसमेंट उपलब्धि की जानकारी देते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। श्री यादव ने केपीएमजी कनाडा में एक करोड़ प्रति वर्ष का वार्षिक पैकेज प्राप्त किया है, जहाँ वे मैनेजर झु साइबर सिक्नोरिटी के पद पर कार्यरत हुए हैं। यह उत्कृष्ट उपलब्धि श्री यादव की मजबूत तकनीकी दक्षता, निरंतर समर्पण एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता का प्रतिफल है। यह उपलब्धि केएनएमआईटी की शैक्षणिक उत्कृष्टता, उद्योग-उन्मुख शिक्षा एवं



विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर दिए जा रहे बल की भी साक्षी है। डॉ. के. एन. मोदी फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) डी. के. मोदी ने वैभव यादव को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल एवं सफल व्यावसायिक भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विद्यार्थी की उपलब्धि पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और उनकी कड़ी मेहनत तथा दृढ़

संकल्प की सराहना की। केएनएमआईटी में आयोजित 'अलमनाई स्पॉक्स' कार्यक्रम, जिसका समन्वय डॉ. के. एन. मोदी फाउंडेशन के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी श्री अजय प्रजापति द्वारा किया गया। वैभव यादव ने विद्यार्थियों से संवाद किया और अपने शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अनुभवों से उपयोगी मार्गदर्शन साझा किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने



संबंधित क्षेत्रों में मजबूत आधार बनाने, निरंतर प्रयासरत रहने तथा तकनीकी, संचार एवं समस्या-समाधान कौशल का सक्रिय विकास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें अपनी रोजगार-योग्यता बढ़ाने हेतु इंटरनशिप, प्रोजेक्ट, प्रमाणन एवं उद्योग-अनुभव का अधिकतम लाभ उठाने की सलाह भी दी। उनके संवाद ने विद्यार्थियों को अत्यधिक प्रेरित किया, जिन्हें करियर

नियोजन, वैश्विक अवसरों तथा व्यावसायिक उत्कृष्टता की प्राप्ति में हृदय के महत्व पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अपनी इस यात्रा के दौरान वैभव यादव ने केएनएमआईटी के निदेशक प्रो. (डॉ.) शिशिर रस्तोगी से भी एआई-नेटिव साइबर सिक्नोरिटी सिस्टम तथा पोस्ट-क्वांटम साइबर सिक्नोरिटी परिदृश्य के उभरते रुझानों पर ज्ञानवर्धक चर्चा की। उन्होंने चर्चा की कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार खतरा पहचान, स्वचालित घटना-प्रतिक्रिया एवं अनुकूली रक्षा तंत्र को नया आकार दे रही है। साथ ही, क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम एवं भविष्य-तैयार सुरक्षा आर्किटेक्चर की बढ़ती आवश्यकता पर भी बल दिया गया। श्री यादव ने उन्नत तकनीकी शिक्षा पर संस्थान के फोकस की सराहना की तथा

विद्यार्थियों को एआई-आधारित सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी एवं अगली पीढ़ी के साइबर रक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। केएनएमआईटी के संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने भी श्री यादव को इस उपलब्धि पर बधाई दी तथा उनके भविष्य के सभी प्रयासों में सतत सफलता की कामना की। यह उपलब्धि प्रतिभाओं को निखारने, तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सार्थक करियर हेतु तैयार करने के संस्थान के निरंतर प्रयासों की और मजबूती प्रदान करती है। केएनएमआईटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर सृजित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

सपा के एमएलसी मतदान के लिए कैप कार्यालय का किया सफलता पूर्वक संचालन



अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। मेरठ सहारनपुर खंड शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के एमएलसी शिक्षक प्रत्याशी डॉ नितिन तोमर एवं स्नातक प्रत्याशी परविंदर सिंह भाटी के चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मोदी इंटर कॉलेज में मतदान के लिए कैप कार्यालय का सफलता पूर्वक संचालन किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश महासचिव समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश एवं मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े गिरीश मथुरिया सैनी के साथ पूर्व राज्य मंत्री रमेश प्रजापति, नगर अध्यक्ष

सचिन दीक्षित जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा, पूर्व मंत्री रामकिशोर अग्रवाल, प्रदेश सचिव कालू राम, मोदी वर्मा, तरुण जाटव, शौकीन, फारूक, फिरोज सीकरी, ऋषि शर्मा, जानी चौधरी, संजीव यादव, महावीर गुजर, इस्लाम, सुनील द्विवेदी, उत्तम त्यागी, गुलशन नंदा, कमलेश चौधरी, सायरा बेगम, कृष्णा रहेला आदि बहुत सारे समाजवादी साथी उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इस दौरान पार्टी नेतृत्व के समर्थन में नारे भी लगाए गए।

‘भारत को जानो’ प्रतियोगिता में डीपीएस मोदीनगर का शानदार प्रदर्शन, 16 विद्यालयों में द्वितीय स्थान

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। भारत विकास परिषद, मोदीनगर द्वारा विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित प्रतिष्ठित प्रतियोगिता ह्यभारत को जानोह् में दिल्ली पब्लिक स्कूल मोदीनगर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 16 विद्यालयों में द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित लिखित परीक्षा में विद्यार्थियों के भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, परंपराओं, राष्ट्रीय विरासत एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित ज्ञान का आकलन किया गया। डीपीएस मोदीनगर के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, ज्ञान एवं आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय को यह उल्लेखनीय उपलब्धि दिलाई। विद्यालय की ओर से कक्षा आठ के विद्यार्थी युगल शर्मा एवं कार्तिक



धामा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अगले चरण के लिए चयनित हुए। दोनों विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन एवं भारत की समृद्ध विरासत के प्रति गहन रुचि का परिचय देते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। इस शानदार उपलब्धि पर डॉ. विक्रम गांधी (सचिव डीएमईटी) एवं श्रीमति अनीशा गांधी (प्रो-वाइस चैयरपर्सन दिल्ली पब्लिक स्कूल) ने युगल शर्मा एवं कार्तिक धामा को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं

विद्यार्थियों में ज्ञान, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को सुदृढ़ करती हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. ज्योति सिरौही ने दोनों प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह उपलब्धि डीपीएस मोदीनगर की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ज्ञानवान, आत्मविश्वासी, जागरूक एवं राष्ट्र की गौरवशाली विरासत से जुड़े जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित किया जाता है।

धर्मपत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे सरदार एसपी सिंह, डाला वोट



वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। एमएलसी स्नातक निर्वाचन के दौरान शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य सरदार एसपी सिंह ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सतनाम कौर के साथ राजनगर स्थित इग्राहम इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मतधिकार का प्रयोग किया। दोनों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदान किया। स्नातक निर्वाचन में मतदान करने पहुंचे सरदार एसपी सिंह ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतधिकार

के महत्व को रेखांकित किया। चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। मतदान के माध्यम से मतदाता अपने प्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया में योगदान देता है। सरदार एसपी सिंह ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान नागरिकों का महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका जिम्मेदारी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने मतदाताओं से बिना किसी संकोच के मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने का आह्वान किया।

निजी पलों के वीडियो पोर्न साइटों पर अपलोड, दंपति के उड़े होश

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। मोबाइल में सुरक्षित निजी पलों की तस्वीरें और वीडियो अश्लील वेबसाइटों पर प्रसारित होने की जानकारी मिलने पर एक दंपति के होश उड़ गए। मधुवन बापूधाम थाना क्षेत्र निवासी महिला ने अज्ञात व्यक्ति पर उनके और पति के निजी फोटो व वीडियो विभिन्न अश्लील वेबसाइटों पर अपलोड करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके मोबाइल फोन में पति के साथ के निजी फोटो और वीडियो सुरक्षित थे। आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से कोई अज्ञात व्यक्ति इन तस्वीरों

और वीडियो को विभिन्न अश्लील वेबसाइटों पर प्रसारित कर रहा है। इसकी जानकारी होने पर दंपति परेशान हो गए। महिला का कहना है कि इस घटना से उन्हें सामाजिक बदनामी की चिंता के साथ मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। महिला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से जांच कर निजी सामग्री इंटरनेट पर अपलोड करने वाले व्यक्ति की पहचान करने और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि निजी फोटो और वीडियो किसने, कब और किस माध्यम से वेबसाइटों पर साझा किए।

स्नातक एवं शिक्षक के चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधान परिषद स्नातक व शिक्षक सीट के लिए मतदाताओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। मेरठ- सहारनपुर खंड विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक सीट के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधान परिषद स्नातक व शिक्षक सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अपील



की। मोदीनगर में दो मतदान स्थल पर वोट डाले गए।

मतदान केंद्रों पर राजनीतिक पार्टी के लगाए गए शिबिर पर कार्यकर्ताओं अपने वोट की पर्ची बनवाते नजर आए। भाजपा के शिबिर पर काफी

भीड़ नजर आई। भाजपा शिबिर पर विधायक डॉ मंजू शिवाच, पालिका अध्यक्ष विनोद वैशाली, वरिष्ठ नेता डॉ मेरी पत्नी ने वोट दिया और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भारी मत से दिनेश गोयल को जीत मिले।

शिव अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी, महामंत्री सभासद ललित त्यागी, नगर अध्यक्ष आकाश शर्मा, जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर गौरव माहेश्वरी, सुवि नेता मयंक शर्मा, प्यसन शर्मा, शिवान गुप्ता, दीपांशु मलिक आदि कार्यकर्ताओं में शिबिर में सफलतापूर्वक संचालन किया और मतदाताओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। भाजपा युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष शिव अग्रवाल ने कहा कि भाजपा एमएलसी स्नातक उम्मीदवार दिनेश गोयल को मैंने और मेरी पत्नी ने वोट दिया और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भारी मत से दिनेश गोयल को जीत मिले।

परशुराम परिषद के प्रदेश महामंत्री दीपक वत्स को जन्म दिवस पर दी बधाई एवं शुभकामनाएं



वेलकम इंडिया संवाददाता

मोदीनगर। समाजसेवी, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व सभासद दीपक वत्स के

जन्म दिवस पर उनके निवास स्थान पर पहुंचकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु की कामना की।

आईपेक और बीईएल के बीच हुआ एमओयू, रक्षा तकनीक और शोध को मिलेगा बढ़ावा



वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज (आईपेक) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी (सीआरएल), गाजियाबाद के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। आई-दिशा पहल के तहत हुए इस समझौते से शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ेगा। साथ ही विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, शोध और कौशल विकास के नए अवसर मिलेंगे। समझौते का

मुख्य उद्देश्य तकनीकी शोध को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। इसके तहत दोनों संस्थान उभरती तकनीकों, इंजीनियरिंग और संयुक्त शोध एवं विकास परियोजनाओं पर मिलकर काम करेंगे। रक्षा क्षेत्र के साथ नागरिक इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी नई तकनीकों के विकास पर जोर दिया जाएगा।

इस साझेदारी से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ तकनीकी क्षेत्र में व्यावहारिक जानकारी हासिल करने

का अवसर मिलेगा। उद्योग और शिक्षण संस्थान के बीच बेहतर तालमेल से विद्यार्थियों को नई तकनीकों को समझने और अपने कौशल को निखारने में मदद मिलेगी। आई-दिशा पहल के तहत किया गया यह समझौता गाजियाबाद में शोध और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे कॉलेज और उद्योग के बीच सहयोग मजबूत होने के साथ भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप काम करने का रास्ता भी तैयार होगा।

दिल्ली में धरने-नाकेबंदी ने ठप किया कारोबार का पहिया, त्योहारों की चमक फीकी; व्यापारियों को 3400 करोड़ की चपत

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद/नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अक्टूबर के महीने में लगातार हो रहे राजनीतिक धरने-प्रदर्शनों और रास्तों की नाकाबंदी ने दिल्ली के पूरे व्यापारिक तंत्र की कमर तोड़कर रख दी है। त्योहारों के इस मुख्य सीजन में बाजारों की रोक-गायब हो चुकी है और व्यापारियों को रोजाना करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। देश में व्यापारियों की अग्रणी संस्था 'व्यापारी एकता समिति संस्थान' के ताजा अनुमान के अनुसार, अक्टूबर महीने में हुए विरोध प्रदर्शनों, मुख्य सड़कों की नाकाबंदी, मेट्रो स्टेशनों के बार-बार बंद होने और सेंट्रल पार्क जैसे प्रमुख व्यावसायिक स्थलों के बंद रहने के कारण दिल्ली के कारोबार को अब तक ३400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बड़ा नुकसान हो चुका है। अक्टूबर का महीना दिल्ली के व्यापारियों के लिए पूरे साल का सबसे अहम और कमाई वाला समय होता है। इस दौरान नवरात्रि, रामलीला और दीपावली जैसे बड़े त्योहार एक



के बाद एक आते हैं। सामान्य दिनों की तुलना में इस समय बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ती है। न केवल दिल्ली-पुनसीआर के लोग, बल्कि देश के कोने-कोने और अलग-अलग राज्यों से व्यापारी भी आम खरीदार थोक व खुदरा खरीदारी के लिए दिल्ली के बाजारों का रुख करते हैं। व्यापारी एकता समिति संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा अक्टूबर का यह समय हमारे लिए पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी दौर होता है। पूरे साल व्यापारी इस सीजन का इंतजार करते हैं ताकि वे अपना पिछला घाटा पूरा कर सकें।

मतदाता सूची में नाम नहीं तो शनिवार-रविवार को बूथ पर पहुंचे, छूटे लोगों को मिलेगा मौका

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित रह गए लोगों और पहली बार मतदान के लिए पात्र युवाओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए जिले में शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। 24 और 25 अक्टूबर को जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उपस्थित रहकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और प्रविष्टियों में संशोधन से संबंधित आवेदन प्राप्त करेंगे। प्रशासन ने पात्र मतदाताओं से अभियान का लाभ उठाने की अपील की है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र लोगों के नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भरवाया जाएगा। वहीं, मतदाता सूची में नाम अथवा अन्य विवरण में त्रुटि होने या निवास स्थान बदलने की स्थिति में फार्म-8 के माध्यम से



आवेदन किया जा सकेगा। विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के तहत तैयार एएसडीटी सूची में शामिल ऐसे व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा, जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। सत्यापन में पात्र पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति से फार्म-6 भरवाकर नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रशासन का जोर पात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें सूची में शामिल करने पर है।

अंजनी कुमार सिंह ने सभी सुपरवाइजरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित करें और उनके कार्यों की निगरानी करें। सुपरवाइजर क्षेत्र में भ्रमण कर छूटे हुए पात्र मतदाताओं के आवेदन जमा कराने में भी सहयोग करेंगे।

इसके अलावा सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेत्रों में अभियान का प्रचार-प्रसार कराते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। जिन विभागों के कर्मचारियों को बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया है, उनके कार्यालयधक्षकों का भी 24 और 25 अक्टूबर को विशेष अभियान के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और नाम दर्ज नहीं होने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करें।

